

The background of the journal cover features a top-down view of a desk. On the left, a pair of black leather brogue shoes is partially visible. In the center, an open notebook with lined pages and a silver pen lies on a light-colored wooden surface. To the right, a black leather bag with a zipper and a black leather watch with a silver face are also visible. A large, semi-transparent white rectangular box is centered over the image, containing the journal's title and ISSN information.

INTERNATIONAL LAW  
JOURNAL

---

**WHITE BLACK  
LEGAL LAW  
JOURNAL**  
**ISSN: 2581-  
8503**

*Peer - Reviewed & Refereed Journal*

The Law Journal strives to provide a platform for discussion of International as well as National Developments in the Field of Law.

[WWW.WHITEBLACKLEGAL.CO.IN](http://WWW.WHITEBLACKLEGAL.CO.IN)

## DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, translated, or distributed in any form or by any means—whether electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise—without the prior written permission of the Editor-in-Chief of *White Black Legal – The Law Journal*.

All copyrights in the articles published in this journal vest with *White Black Legal – The Law Journal*, unless otherwise expressly stated. Authors are solely responsible for the originality, authenticity, accuracy, and legality of the content submitted and published.

The views, opinions, interpretations, and conclusions expressed in the articles are exclusively those of the respective authors. They do not represent or reflect the views of the Editorial Board, Editors, Reviewers, Advisors, Publisher, or Management of *White Black Legal*.

While reasonable efforts are made to ensure academic quality and accuracy through editorial and peer-review processes, *White Black Legal* makes no representations or warranties, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the content published. The journal shall not be liable for any errors, omissions, inaccuracies, or consequences arising from the use, interpretation, or reliance upon the information contained in this publication.

The content published in this journal is intended solely for academic and informational purposes and shall not be construed as legal advice, professional advice, or legal opinion. *White Black Legal* expressly disclaims all liability for any loss, damage, claim, or legal consequence arising directly or indirectly from the use of any material published herein.

## ABOUT WHITE BLACK LEGAL

*White Black Legal – The Law Journal* is an open-access, peer-reviewed, and refereed legal journal established to provide a scholarly platform for the examination and discussion of contemporary legal issues. The journal is dedicated to encouraging rigorous legal research, critical analysis, and informed academic discourse across diverse fields of law.

The journal invites contributions from law students, researchers, academicians, legal practitioners, and policy scholars. By facilitating engagement between emerging scholars and experienced legal professionals, *White Black Legal* seeks to bridge theoretical legal research with practical, institutional, and societal perspectives.

In a rapidly evolving social, economic, and technological environment, the journal endeavours to examine the changing role of law and its impact on governance, justice systems, and society. *White Black Legal* remains committed to academic integrity, ethical research practices, and the dissemination of accessible legal scholarship to a global readership.

## AIM & SCOPE

The aim of *White Black Legal – The Law Journal* is to promote excellence in legal research and to provide a credible academic forum for the analysis, discussion, and advancement of contemporary legal issues. The journal encourages original, analytical, and well-researched contributions that add substantive value to legal scholarship.

The journal publishes scholarly works examining doctrinal, theoretical, empirical, and interdisciplinary perspectives of law. Submissions are welcomed from academicians, legal professionals, researchers, scholars, and students who demonstrate intellectual rigour, analytical clarity, and relevance to current legal and policy developments.

The scope of the journal includes, but is not limited to:

- Constitutional and Administrative Law
- Criminal Law and Criminal Justice
- Corporate, Commercial, and Business Laws
- Intellectual Property and Technology Law
- International Law and Human Rights
- Environmental and Sustainable Development Law
- Cyber Law, Artificial Intelligence, and Emerging Technologies
- Family Law, Labour Law, and Social Justice Studies

The journal accepts original research articles, case comments, legislative and policy analyses, book reviews, and interdisciplinary studies addressing legal issues at national and international levels. All submissions are subject to a rigorous double-blind peer-review process to ensure academic quality, originality, and relevance.

Through its publications, *White Black Legal – The Law Journal* seeks to foster critical legal thinking and contribute to the development of law as an instrument of justice, governance, and social progress, while expressly disclaiming responsibility for the application or misuse of published content.

# **भारत में व्यावसायिक विधियों का विनियामक अवलोकन**

**\*ब्यूटी कुमारी, सेज विश्वविद्यालय, इंदौर।**

## **सार (Abstract)**

भारत के व्यावसायिक परिदृश्य में पिछले तीन दशकों के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है, जिसका प्रमुख कारण आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा तीव्र तकनीकी विकास रहा है। भारत में व्यावसायिक विधियों को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढाँचा समय-समय पर बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है, जिससे आर्थिक विकास और कानूनी उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके। यह शोध-पत्र भारत में व्यावसायिक विधियों की विनियामक संरचना का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है, जिसमें कंपनी विधि, संविदा विधि, प्रतिस्पर्धा विधि, बौद्धिक संपदा विधि तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संबंधी व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है।

यह अध्ययन विभिन्न नियामक संस्थाओं तथा न्यायपालिका की भूमिका का भी परीक्षण करता है, जो इन विधियों के प्रवर्तन और बाजार अनुशासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त, शोध-पत्र वर्तमान व्यवस्था में विद्यमान चुनौतियों जैसे विनियामक अतिव्यापन, अनुपालन संबंधी जटिलताओं तथा विवाद निपटान में विलंब पर प्रकाश डालता है। अंततः यह शोध-पत्र कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, संस्थागत दक्षता बढ़ाने तथा भारत के व्यावसायिक कानूनों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने हेतु आवश्यक सुधारों का सुझाव देता है, ताकि निवेश और उद्यमिता के लिए अधिक अनुकूल वातावरण निर्मित किया जा सके।

## **1. प्रस्तावना (Introduction)**

भारत में व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढाँचा एक जटिल किंतु सुव्यवस्थित प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा साथ ही पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। व्यावसायिक विधियाँ केवल कानूनी प्रावधानों का समूह नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी रणनीतिक संरचना हैं जो बाजारों के संचालन को निर्धारित करती हैं, निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करती हैं तथा व्यवसाय करने की सुगमता को आकार देती हैं।

वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के आगमन के साथ भारत ने नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण किया। इस परिवर्तन ने एक ऐसे सशक्त और अनुकूलनशील कानूनी ढाँचे की आवश्यकता उत्पन्न की जो उभरती हुई व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। इस प्रक्रिया में राज्य की भूमिका प्रत्यक्ष आर्थिक भागीदारी से बदलकर निजी उद्यमों के नियामक और सहायक के रूप में विकसित हुई।

व्यावसायिक विधियों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे व्यापारिक लेन-देन के लिए एक सुरक्षित एवं पूर्वानुमेय वातावरण निर्मित करती हैं। ये विधियाँ व्यवसायिक पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित करती हैं, विवाद समाधान की व्यवस्था प्रदान करती हैं तथा कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिक आचरण के मानक स्थापित करती हैं। साथ ही, इनका उद्देश्य निवेशकों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों तथा ऋणदाताओं जैसे विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा करना भी है, जिससे आर्थिक विकास सामाजिक न्याय की कीमत पर न हो।

हालाँकि, महत्वपूर्ण सुधारों के बावजूद भारत की विनियामक व्यवस्था अभी भी प्रक्रियात्मक जटिलताओं, बहुविध कानूनों तथा प्रवर्तन संबंधी अक्षमताओं जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। यह शोध-पत्र भारत की व्यावसायिक विधियों की संरचना, क्षेत्र तथा प्रभावशीलता का विश्लेषण करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास करता है जहाँ सुधारों की आवश्यकता है।

## **2. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)**

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारत में व्यावसायिक विधियों के विनियामक ढाँचे की व्यापक समझ विकसित करना तथा व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। यह शोध-पत्र उन प्रमुख विधियों का परीक्षण करता है जो व्यवसायिक विनियमन की आधारशिला हैं तथा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका का विश्लेषण करता है।

इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन व्यवसायों द्वारा इन विधियों के अनुपालन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करने तथा समकालीन मुद्दों के समाधान हेतु वर्तमान विनियामक तंत्र की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। साथ ही, यह शोध-पत्र कानूनी ढाँचे को अधिक सरल, सुलभ और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए व्यावहारिक एवं दूरदर्शी सुझाव प्रस्तुत करता है।

## **3. अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)**

यह शोध मुख्यतः सैद्धांतिक अथवा डॉक्ट्रिनल अनुसंधान पद्धति पर आधारित है, जिसमें वैधानिक प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों, पुस्तकों, शोध-पत्रों तथा सरकारी रिपोर्टों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। यह पद्धति व्यावसायिक विधियों के वैचारिक और कानूनी पहलुओं को समझने के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से विधायी उद्देश्य, न्यायिक व्याख्या तथा व्यावहारिक क्रियान्वयन का विस्तृत परीक्षण संभव होता है।

अध्ययन गुणात्मक आँकड़ों पर आधारित है तथा विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के समन्वय के माध्यम से यह शोध भारत की व्यावसायिक विधियों तथा उनके आर्थिक प्रभाव का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

## **4. भारत में व्यावसायिक विधियों का विकास (Evolution of Business Laws in India)**

भारत में व्यावसायिक विधियों का विकास देश के आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का दर्पण रहा है। उदारीकरण से पूर्व की अवधि में विनियामक ढाँचा अत्यधिक सरकारी नियंत्रण पर आधारित था। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 जैसी विधियों का उद्देश्य आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना तथा संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना था।

उस समय “लाइसेंस राज” व्यवस्था के अंतर्गत निजी उद्यमों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा और नवाचार सीमित हो गए थे। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की व्यावसायिक नीति में ऐतिहासिक परिवर्तन लाया। सरकार का ध्यान नियंत्रण से हटकर सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित हुआ। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश आकर्षित

करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से अनेक नई विधियाँ लागू की गईं तथा पुरानी विधियों में संशोधन किए गए।

हाल के वर्षों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 तथा वस्तु एवं सेवा कर जैसी व्यवस्थाओं ने भारत के व्यावसायिक वातावरण को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

## **5. भारत की प्रमुख व्यावसायिक विधियाँ (Key Business Laws in India)**

भारत की व्यावसायिक विधियों का ढाँचा अनेक प्रमुख अधिनियमों से मिलकर बना है, जो व्यापारिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों के गठन, प्रबंधन तथा विघटन को नियंत्रित करने वाली प्रमुख विधि है। यह कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए विस्तृत ढाँचा प्रदान करता है, जिसमें निदेशकों के कर्तव्य, प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएँ तथा अल्पसंख्यक शेयरधारकों की सुरक्षा जैसे प्रावधान सम्मिलित हैं।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 व्यापारिक लेन-देन की आधारशिला है। यह संविदाओं के निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तन के सिद्धांतों को परिभाषित करता है तथा व्यवसायिक संबंधों में निश्चितता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इस अधिनियम के प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी है।

बौद्धिक संपदा संबंधी विधियाँ जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कानून नवाचार और रचनात्मकता की रक्षा करती हैं। ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में इन विधियों का महत्व अत्यंत बढ़ गया है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ने वित्तीय संकट के समाधान हेतु एक समयबद्ध और प्रभावी प्रणाली प्रदान की है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या को कम करने में सहायता मिली है।

## **6. नियामक संस्थाएँ और संस्थागत ढाँचा (Regulatory Bodies and Institutional Framework)**

भारत में व्यावसायिक विधियों के प्रवर्तन का कार्य विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी कानूनों के अनुपालन की निगरानी करता है, जबकि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है।

ये संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं, किंतु कई बार समन्वित रूप से भी कार्य करती हैं ताकि प्रभावी नियमन सुनिश्चित किया जा सके।

## **7. व्यावसायिक विनियमन में न्यायपालिका की भूमिका (Role of Judiciary in Business Regulation)**

न्यायपालिका भारतीय कानूनी व्यवस्था की संरक्षक है और व्यावसायिक विधियों की व्याख्या एवं प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायालय विधायी प्रावधानों की व्याख्या करते हैं, विवादों का समाधान करते हैं तथा न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखते हैं।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलिय अधिकरण जैसे विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना ने कॉर्पोरेट विवादों के निपटान को अधिक प्रभावी बनाया है। तथापि, मामलों की लंबित संख्या तथा न्यायिक विलंब अब भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

## **8. विनियामक ढाँचे की चुनौतियाँ (Challenges in the Regulatory Framework)**

भारत की व्यावसायिक विनियामक व्यवस्था ने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी इसमें अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विभिन्न कानूनों और नियामक संस्थाओं की बहुलता के कारण कई बार अधिकार क्षेत्र में अतिव्यापन और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यवसायों को अनेक प्रकार के अनुपालन दायित्वों का पालन करना पड़ता है, जिससे लागत और प्रशासनिक बोझ बढ़ता है।

इसके अतिरिक्त, विवादों के समाधान और संविदाओं के प्रवर्तन में देरी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करती है। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति ने नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं, विशेषकर डिजिटल वाणिज्य और वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, जहाँ वर्तमान कानून कई बार अपर्याप्त सिद्ध होते हैं।

## **9. सरकारी पहल और सुधार (Government Initiatives and Reforms)**

हाल के वर्षों में सरकार ने व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने हेतु अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं। प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटल अनुपालन प्रणाली तथा लघु अपराधों के अपराधीकरण को समाप्त करने जैसे उपायों ने व्यावसायिक वातावरण को अधिक अनुकूल बनाया है।

ऑनलाइन कंपनी पंजीकरण और कर भुगतान प्रणालियों ने अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया है। “स्टार्टअप इंडिया” जैसी योजनाओं ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया है।

## **10. तुलनात्मक दृष्टिकोण (Comparative Perspective)**

विकसित देशों की तुलना में भारत की व्यावसायिक विधि व्यवस्था में कई मजबूत पक्ष मौजूद हैं, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, व्यापक कानूनी ढाँचा और तेजी से विकसित हो रही डिजिटल संरचना। हालांकि, प्रक्रियात्मक विलंब और जटिल अनुपालन व्यवस्थाएँ अभी भी इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

भारत ने वैश्विक “Ease of Doing Business” सूचकांकों में अपनी स्थिति में सुधार किया है, किंतु अभी भी और अधिक सुधारों की आवश्यकता है।

## **11. सुझाव और अनुशंसाएँ (Suggestions and Recommendations)**

व्यावसायिक विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि कानूनों को सरल बनाया जाए तथा विनियामक अतिव्यापन को कम किया जाए। नियामक संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करके अनुपालन और विवाद समाधान प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, व्यवसायों के बीच कानूनी जागरूकता बढ़ाने तथा नवाचार आधारित क्षेत्रों के लिए लचीली और अनुकूलनशील विधियों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

## **12. निष्कर्ष (Conclusion)**

भारत की व्यावसायिक विधियों का विनियामक ढाँचा देश की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है तथा पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। यद्यपि पिछले वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, फिर भी प्रक्रियात्मक जटिलताओं, प्रवर्तन संबंधी समस्याओं तथा संस्थागत चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

यदि भारत अपने कानूनी ढाँचे को अधिक सरल, प्रभावी और नवाचारोन्मुख बना सके, तो वह वैश्विक निवेश और उद्यमिता के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकता है।

## **अंत टिप्पणियाँ (Endnotes)**

1. कंपनी अधिनियम, 2013।
2. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872।
3. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002।
4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016।
5. एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969।
6. भारत का संविधान, 1950।
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992।
8. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934।
9. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी विधि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (भारत सरकार, 2005)।
10. दिवाला विधि सुधार समिति, दिवाला विधि सुधार समिति की रिपोर्ट (भारत सरकार, 2015)।
11. भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 (वित्त मंत्रालय, 2023)।
12. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 (सीसीआई, 2022)।
13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 (सेबी, 2023)।
14. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट 2022-23 (आरबीआई, 2023)।
15. Salomon v A Salomon & Co Ltd।
16. Foss v Harbottle।

17. LIC of India v Escorts Ltd।
18. ICICI Bank v Official Liquidator of APS Star Industries Ltd।
19. Swiss Ribbons Pvt Ltd v Union of India।
20. Innoventive Industries Ltd v ICICI Bank।
21. अवतार सिंह, कंपनी विधि (17वाँ संस्करण, ईस्टर्न बुक कंपनी 2018)।
22. एम.सी. कुच्छल एवं विवेक कुच्छल, व्यावसायिक विधि (8वाँ संस्करण, विकास पब्लिशिंग 2019)।
23. टैक्समैन, कॉर्पोरेट विधियाँ (टैक्समैन पब्लिकेशन्स 2022)।
24. रामैया, कंपनी अधिनियम मार्गदर्शिका (लेक्सिसनेक्सिस 2021)।
25. अनिरुद्ध वाघवा, 'भारत में प्रतिस्पर्धा विधि : विकास और प्रभावशीलता' (2020) 12 इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स 45।
26. उमाकांत वरोट्टिल, 'भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन : स्वैच्छिक प्रकटीकरण से अनिवार्य प्रकटीकरण की ओर संक्रमण' (2012) 7 नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया रिव्यू 1।
27. विश्व बैंक, डूइंग बिजनेस 2020 : 190 अर्थव्यवस्थाओं में व्यावसायिक विनियमन की तुलना (विश्व बैंक 2020)।
28. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ओईसीडी आर्थिक सर्वेक्षण : भारत 2021 (ओईसीडी पब्लिशिंग 2021)।
29. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, दिवाला और शोधन अक्षमता वाद संग्रह (2022)।
30. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना रिपोर्ट (भारत सरकार 2016)।